

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,  
प्रभारी सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक/3 अप्रैल, 2017

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में नगर निगम, हरिद्वार को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार के पत्रांक-375/नि0वि0/2016-17, दिनांक 27.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, हरिद्वार के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन कुल ₹ 47.57 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) की संस्तुतिनुसार कुल ₹ 40.81 लाख (रुपये चालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि
1.	कडक मोहल्ला में खेडा मंदिर से सोमपाल के मकान तक सी0सी0 सड़क, नाली कासिंग पुलिया का निर्माण, वार्ड नं0-1	5.11
2.	टिबडी शिवलोक कालोनी, जनता क्वार्टर के अन्दर की गलियों का सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण कार्य, वार्ड नं0-3	6.51
3.	ब्रह्मपुरी में डा0 मेहता के मकान से कमला के मकान तक नाला पुनर्निर्माण कार्य, वार्ड नं0-6	12.06
4.	कोटरावान में उमेश गर्ग के घर से पार्षद निवास तक सड़क/नाली निर्माण, वार्ड नं0-7	6.01
5.	सोन्धी वाली गली के पारुल चौहान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण, वार्ड नं0-14	11.12
योग-		40.81

2- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

- उक्त धनराशि कुल ₹ 40.81 लाख (रुपये चालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

- (v) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- (vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- (viii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (ix) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (x) उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।
- (xi) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- (xii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (xiii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- (xiv) धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xvi) धनराशि का दिनांक 31-3-2018 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3- उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-51-निर्माण-04-नगरों का समेकित विकास-01-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 02/XXVII(2)/2017, दिनांक 10.04.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-अलॉटमेंट आई डी-S.I./2017/30235

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)  
प्रभारी सचिव।



सं०-332 (1)/IV(2)-शा0वि0-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0आ0 में इसे शामिल करें।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(डी0एम0एस0 राणा)

उप सचिव।

